देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 15 अंक: 48 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...मामला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण

पेज थ्री

देहरादून, शनिवार, 16 मई 2020

मौसम अधिकतम 36.0° न्यूनतम 21.0°

31097.73 | 2 सागर के रास्ते भारत को घेर रहा चीन | 7 जिंदगी का सबसे भयानक समयः शास्त्री

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली में कम तीव्रता का भूकंप, 12 अप्रैल के बाद से चौथा भूकंप

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को 2.2 की कम तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि 12 अप्रैल के बाद से यह क्षेत्र में आया चौथा भूकंप है। भूकंप का केंद्र उत्तरी दिल्ली के पीतमपुरा में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि यह भूकंप 11 बजकर 28 मिनट पर आठ किलोमीटर की गहराई में आया। यह केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक निकाय है।

कोरोना केस 81 हजार पार

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह तक कुल केसों की संख्या 81970 हो गई। कोरोना से अबतक 27920 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 2649 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। कोरोना की रोकथाम के लिए लगाया गया लॉकडाउन 3.0 रविवार को खत्म हो रहा है। 18 मई से लॉकडाउन 4.0 किस तरह का होगा इसपर कोई साफ निर्देश नहीं आया है।

डॉक्टरों के लिए इंतजाम, सुको ने केंद्र से पूछा

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह बताए कि डॉक्टरों को अस्पताल के नजदीक रखने का इंतजाम हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक डॉक्टर की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि कोविड-19 से लड़ने वाले डॉक्टरों के लिए अस्पताल के पास रहने की सुविधा होनी चाहिए नहीं तो कोरोना वॉरियर ही लड़ाई हार जाएंगे। डॉक्टरों के रहने के बारे में एक एसओपी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे तब तक सॉलिसिटर जनरल अस्पताल के बाहर डॉक्टरों के लिए क्वारंटीन सुविधाएं देने के बारे में सरकार से निर्देश लेकर आएं।

कृषि क्षेत्र के लिए पैकेज का ऐलान

इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर कानून में सुधार की रूपरेखा पेश की

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनाज, खाद्य तेलों, तिलहन, दालें, प्याज, आलू आदि को आवश्यक वस्तु कानून के दायरे से बाहर निकालने का बड़ा फैसला किया है। सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें अपने उत्पाद कहीं भी बेच पाने की अनुमति देने वाले कानूनी सुधार की भी ऐलान किया। ये घोषणाएं आत्मनिर्भर अभियान के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के विस्तृत ब्योरे के लगातार तीसरे दिन की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान की गई।

वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के कारण दबाव में आए खेती और सहायक गतिविधियों मसलन मछलीपालन और पशुपालन आदि के लिए पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए 11 कदमों की घोषणा की।

1. एक लाख करोड़ रुपये का फार्म-गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडः कोल्ड स्टोरेज, फसल कटाई के बाद मैनेजमेंट आदि के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड जल्द ही बनाया जाएगा। इससे भंडारण और मूल्य संवर्धन की समस्या खत्म हो जाएगी।

2. माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज के फॉर्मलाइजेशन के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की स्कीमः इस योजना से 2 लाख छोटी एमएफई को फायदा होगा।

3. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये।

4. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम।

5. पशुपालन के आधारभूत ढांचों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का विकास फंड।

6. औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 4 हजार करोड़ रुपये की योजना

7. मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की योजना।

8. टॉप टु टोटल-500 करोड़ रुपयेः इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके तहत अब 50 प्रतिशत सब्सिडी माल ढुलाई में और 50 प्रतिशत सब्सिडी कोल्ड स्टोरेज में भंडारण पर दी जाएगी।

9. बदलेगा आवश्यक वस्तु अधिनियमः इस कानून से किसानों की आय में बढ़ोतरी का संभावना बढ़ जाएगी।

10. किसानों को मनपसंद मार्केटिंग के लिए कृषि विपणन सुधार

11. कृषि उत्पादों की कीमत और गुणवत्ता निर्धारण का ढांचाः किसानों की निश्चित आय, जोखिम रहित खेती, गुणवत्ता के मानकीकरण की दिशा में काम होगा।

किसान के भंडारण की टेंशन दूर, कानूनी सुधार भी, 11 बड़े ऐलान

तमाम मुश्किलों के बावजूद कई कृषि उत्पादों में भारत नंबर 1

वित्त मंत्री ने कहा कि देश की बड़ी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर करती है और ज्यादातर किसान मानसून पर निर्भर हैं। बावजूद इसके देश दूध, जूट, दाल आदि के उत्पादन में दुनिया में टॉप है। वहीं, ईख, कपास, मूंगफली, फल और मछली उत्पादन के मामले में हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर है जबकि अन्न (सीरियल्स) उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने बताया कि देशभर में रबी फसलों की कटाई लगभग हो चुकी है। अनाज की सरकारी खरीद भी बड़े पैमाने पर हो चुकी है और प्रक्रिया जा रही है।

कोरोना पेशेंट मिला, सेना भवन का हिस्सा बंद

सैनिटाइजेशन के बाद ही खुलेगा, यहां से एक संदिग्ध मरीज की भी हुई पहचान

संवाददाता

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की चपेट में भारतीय सेना का मुख्यालय, सेना भवन भी आ गया है। यहां कोविड-19 का एक कन्फर्म और एक संदिग्ध केस सामने आया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि इसके बाद बिल्डिंग के उस फ्लोर के एक हिस्से को बंद कर दिया गया है। अब वहां पर सैनिटाइजेशन और फ्यूमिगेशन किया जाएगा ताकि वायरस के ट्रेसेज को खत्म किया जा सके। दिल्ली में स्थित सरकारी भवनों में कोरोना के मरीज मिलने का यह ताजा मामला है। इससे पहले कई मंत्रालयों की इमारतों के हिस्से कोरोना पेशेंट मिलने पर सील किए जा चुके हैं।

सीआरपीएफ, बीएसएफ हेडक्वार्टर भी चपेट में

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ऑफिस राजीव गांधी भवन को कोविड-19 का पेशेंट मिलने पर सील किया गया था। सेंटल रिजर्व पुलिस फोर्स हेडक्वार्टर और बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स हेडक्वार्टर का कुछ हिस्सा भी कोरोना पेशेंट मिलने पर सील हो चुका है। प्रेसिडेंट एस्टेट में अपने परिवार के साथ रहने वाली एक महिला भी कोरोना पॉजिटिव मिली थी।

सील करना पड़ रहा बिल्डिंग का हिस्साः बीते 10 मई को श्रम शक्ति भवन में काम करने वाला एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला था। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया। उससे पहले, 5 मई को शास्त्री भवन के चौथे फ्लोर पर लॉ मिनिस्ट्री के एक अधिकारी में कोरोना की पुष्टि हुई थी। तब 'ए' विंग के गेट नंबर 1 से गेट नंबर 3 के बीच के एरिया को सील किया गया था। नीति आयोग की इमारत पिछले महीने इसी वजह से सील की गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस केसेज की संख्या 8 हजार से ज्यादा हो चुकी है। अब दिल्ली में 8,470 मरीज हो चुके हैं।

सुको ने पूछा, पैदल वालों को रोकने का है हक?

नई दिल्ली। लॉकडाउन के बीच देश के तमाम शहरों से पैदल ही मजदूरों के पलायन और औरंगाबाद ट्रेन हादसे से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल किया कि क्या पैदल चलकर जा रहे मजदूरों को किसी तरह से रोका जा सकता है तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि राज्य सरकारें ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर रही है। पर लोग कई बार गुस्से में आ रहे हैं और पैदल निकल रहे हैं वो इंतजार नहीं कर रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों से सिर्फ ये आग्रह कर सकती है कि वह पैदल न चलें बल्कि ट्रांसपोर्ट ले लें लेकिन अगर कोई मान नहीं रहा तो क्या किया जा सकता है। उन पर बलप्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि इससे लोग रिएक्ट करेंगे। सुको में याचिका दायर कर औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर मजदूरों की मौत का मामला उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल में केंद्र के बयान का हवाला दिया गया, जिसमें केंद्र ने कहा था कि जो भी मजदूर हैं वह पैदल नहीं जा रहे हैं बल्कि प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

क्वारंटीन का समय पूरा जेल भेजे गए 18 जमाती

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

■18 जमातियों में से 8 हैं विदेशी नागरिक

भोपाल। तबलीगी जमात से लौटने वाले जमातियों पर राजधानी भोपाल में कार्रवाई शुरू हो गई। जमात से लौटने के बाद इन लोगों ने जानकारी छिपाई थी। उसके बाद पुलिस ने ऐसे लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। जमातियों की तलाश कर उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। क्वारंटीन का समय पूरा होने के बाद पुलिस जमातियों को जेल भेज रही है।

क्वारंटीन सेंटरों में समय पूरा कर चुके 18 जमातियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए जमातियों पर पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी अधिनियम और लॉकडाउन तोड़ने के मामले दर्ज हैं। मीडिया से बात करते हुए एएसपी मनु व्यास ने कहा कि तलैया, मंगलवारा थाना पुलिस ने 18 जमातियों को गिरफ्तार किया है, इनमें 8 विदेशी हैं।

जेल भेजे गए लोगों में कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, महाराष्ट्र और बिहार के आरोपी हैं। सभी लोगों पर आरोप है कि जानकारी छिपाकर शहर में रह रहे थे, साथ ही धार्मिक आयोजनों में हिस्सा ले रहे थे। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी भोपाल आने से पहले दिल्ली के मरकज में शामिल हुए है।

...तो नेपाल को चीन भड़का रहा है?

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

पिथौरागढ़ में लिपुलेख दर्रे को भारत ने कैलास मानसरोवर रूट से जोड़ा

नई दिल्ली। भारत ने कैलास मानसरोवर तक की यात्रा सुगम करने के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीन-नेपाल बॉर्डर के पास लिपुलेख दर्रे से 5 किलोमीटर पहले तक सड़क बनाई है। इस सड़क के उद्घाटन के बाद नेपाल ने इसे लेकर आपत्ति जतानी शुरू कर दी। हालांकि पहले इस एरिया में नेपाल से कभी विवाद नहीं रहा है।

इंडियन आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि इसकी संभावना है कि नेपाल ऐसा किसी और के इशारे पर कर रहा हो। जनरल नरवणे ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा चीन की तरफ था।

लिपुलेख दर्रे के पास तक सड़क बनाने पर नेपाल की तरफ से जताए गए ऐतराज पर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि मुझे इसे लेकर कोई विवाद नहीं दिखता। जो रोड बनी है वह नदी के पश्चिम की तरफ बनी है। नदी से आगे जब जाते हैं तो ट्राई जंक्शन है।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact: Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in